वर्षों से नहीं निकाला जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) वर्ष 1973 से अब तक डायरेक्टरी और अनुपूरक डायरेक्टरी के अंग्रेजी तथा हिन्दी में कितने कितने अंक निकाले गये हैं और हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रकाशनों के बीच कितना अन्तर होता है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश एक हिन्दी भाषी राज्य है और यदि हां, तो हिन्दी डायरेक्टरी के प्रकाशन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं द्वारा डायरेक्टरी के हिन्दी अंक के बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) मध्य मध्यप्रदेश सर्किल की टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी का पिछला हिन्दी संस्करण जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था;

(ख) 1973 से मध्य प्रदेश सर्किल के लिए अंग्रेजी की एक मुख्य डाइरेक्टरी और छह पूरक डाइरेक्टरियां प्रकाशित हुई थी। जनवरी 1971 के बाद हिन्दी की कोई भी डाइरेक्टरी या उसकी पूरक डाइरेक्टरी नही प्रकाशित हुई है ;

(ग) मुद्रकों और विज्ञापन एजेंटों की नियुक्ति में कुछ अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण हिन्दी टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी के प्रकाशन मे विलंब हुआ है ;

(घ) कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। फ़िर भी, मंडल स्तर पर हिन्दी डाइरेक्टरिया छपवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

राज्य स्तरों पर चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने की योजना

1659. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों ने राज्य स्तर पर चिकित्सा परिषदें स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं पर कौन कौन सी संस्थाएं नियन्त्रण कर रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नही ।

(ख) भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर नियंत्रण रख रहे है ।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Shipping Corporation of India

1660. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total strength of employees in the Shipping Corporation of India and how many among them are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether any shortfall has been noticed in the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in their reserved quota; and

(c) if so, the steps Government have taken to fill up these seats?